

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2002—कार्तिक 8, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 559/1252/वि/नि/चार/2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.
- (2) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.
- समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियाँ जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्वधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द “मध्यप्रदेश” जहाँ कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द “छत्तीसगढ़” स्थापित किए जाएँ.
- अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों के नाम
(1)	(2)
1.	मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973.
2.	मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम, 1974.
3.	मध्यप्रदेश शासन स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा हेतु विनियम, 1961.

Raipur, the 30th October 2002

NOTIFICATION.

No. 559/1252/Fin./Rules/iv/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

- (1) This order may be called the Adaptation order, 2002.
(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.
- The laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh", wherever they occur, the word "Chhattisgarh" shall be substituted.
- Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rules, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No.	Name of the Laws
(1)	(2)
1.	Madhya Pradesh Local Fund Audit Act, 1973.
2.	Madhya Pradesh Local Fund Audit Rules, 1974.
3.	Regulation for the M. P. State Local Fund Audit Subordinate Accounts Service Examination, 1961.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंबोध बिहारी, संयुक्त सचिव.